

प्रेषक,

डा० हेमलता ढौडियाल  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उद्योग,  
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु स्पेशल कम्योनेन्ट सब प्लान तथा ट्राईबल सब प्लान के अधीन धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 882/दजट-08/स्पेशल कम्योनेन्ट/2007-08 दिनांक 8 जून, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु उद्योग निदेशालय के आगोजनागत पक्ष में अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत अनु० जाति/जनजाति कम्योनेन्ट के अधीन जिला योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला योजनान्तर्गत ₹० 2,40,000/- तथा अनुदान सं० 31 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत ₹० 60,000/- अर्थात् कुल ₹० 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) की धनराशि वह संलग्न विवरणानुसार व्यय विनियमों के अन्तर्गत आपकी निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय प्रत्युत्तरिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4- शासनादेश की शर्तों का अनुपालन न करने का सख्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

5- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइवल सब प्लान की योजनाओं के लिये नियोजन विभाग द्वारा मात्राकृत परिव्यय के अनुसार एवं जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा। अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय करने पर समस्त दायित्व सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी का ही होगा। किसी भी दशा में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय।

6- उक्त व्यय सालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अनुदान संख्या-30 एवं 31 के संलग्नक में दिये गये विस्तृत सुसंगत लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामे जाता जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 346/XXVII(2) 2007 दिनांक 31 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भावदीया,

(डा० हेमलता दीक्षिताल)  
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 4117(1)/VII-2/171-उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पीडो/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2
10. गार्ड-फाईल।

जाज्ञा से,

(डा० हेमलता दीक्षिताल)  
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या: 4117/VII-2/171-उद्योग/2006, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-30

(धनराशि लाख रु० में)

2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग-00

आयोजनागत-102-लघु उद्योग-02 अनु० जाति/जनजाति

कम्पौनेन्ट के अधीन जिला योजना-03-उद्यमिता विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिला योजना)

20-सहायक अनुदान/अशदान/राजसहायता ————— 240

अनुदान संख्या-31

2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग-00

आयोजनागत-102-लघु उद्योग-01-अनु०

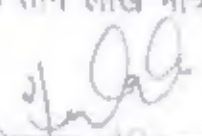
जाति उप योजना-03-उद्यमिता विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम

20-सहायक अनुदान/अशदान/राजसहायता ————— 000

योग: 300

(रु० तीन लाख मात्र)

  
(श्री० हेमलता जैजिवाल)  
अपर सचिव।